श्री हरीश कुमार गंगवार : इससे ज्यादा काम निपट जायेगा ।

Mr. Speaker : Luch hour is suspended at the initiative of Mr. Gangwar. Is it the pleasure of the House to suspend lunch hour ?

Some Hon. Members : Yes.

Shri Satyasadhan Chakraborty (Calcutta South) : See the democracy. When the Prime Minister has gone everybody has gone. Even the Ministers have gone.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Vasant Sathe) : I am Here.

Shri Satyasadhan Chakraborty are just dependent.

Mr. Speaker : Parliamentary democracy is not dependent on anybody. It is dependent on the whole House.

(Interruptions)

(ii) Establishment of an oil terminal at Paradip in Orissa.

Shrimati Jayanti Patnaik (Kendrapara) : The supply of petroleum products to different parts of Orissa has become impossible in the absence of an oil terminal in the State. The State Government has submitted a proposal to Government of India for establishment of an oil terminal at Paradip with a view to streamline the supply of petroleum products to the State. Accordingly Government of India had appointed a Committee which studied the techno-economic viability of having an oil terminal at that Port and already submitted its report. But further action has not been initiated by the Government of India. It is very difficult to maintain sufficient stock of petroleum products if an oil terminal is not set up in the State.

Paradip is the suitable place for having an oil terminal. The supply of petroleum products can be streamlined to the entire State if an oil terminal is set up there. In view of this I demand that the Government of India should expedite the programme for the establishment of an oil terminal at Paradip at the earliest.

(iii) Demand to declare certain blocks of Mirzapur district as industrially backward area.

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं । उत्तर प्रदेश में स्थित मेरा मिर्जापुर जिला लगभग 300 किलोमीटर लम्बा है तथा 100 किलोमीटर चौड़ा है । मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में एक ही तहसील में कोयले की खान तथा बिजली के कारखाने एवं लाइम-स्टोन होने के कारण वहीं पर व्यक्ति गत क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाते हैं।

12.18 hrs.

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में जिले के एक भाग में उद्योग स्थापित होने के कारण सम्पूर्ण जिले की औसत आय तथा औसत राजस्व बढ़ जाने के कारण हमारा मिर्जापुर जिला औद्योगिक पिछड़ेपन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आ पा रहा है, जबकि जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का 75 प्रतिशत जन-समूह गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है । हमारे क्षेत्र का पुराना मिर्जापुर शहर तथा आसपास का ग्रामीण क्षेत्र उजड़ रहा है । शहर के पास तथा तहसील मिर्जापुर में बड़े तथा मझोले उद्योगों का सर्वथा अभाव है । औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित न होने के कारण निजी क्षेत्र में भी कोई उद्यमी मिर्जापुर में उद्योग लगाने को तैयार नहीं , क्योंकि उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्र की सुविधायें नहीं मिलती हैं । स्थिति बहुत दयनीय है । मिर्जापुर नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है । बेरोजगार को काम नहीं मिल रहा है । गरीबी बढ़ रही है । लोग बाहर भाग रहे हैं । परम्परागत उद्योग भी क्षीण हो रहे हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि मिर्जापुर जिले के छानवे, लालगंज, सिटी, हलिया, कोन ब्लाकों को

या मिर्जापुर को सदर तहसील को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाये तथा मिर्जापुर शहर के आसपास कम से कम एक बड़ा तथा कुछ मझोले उद्योग स्थापित किये जायें।

(iv) Relief measures for flood affected areas in katihar district, Bihar.

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय अब तक तो बिहार सूखे से जूझ रहा था किन्तु अब बाढ़ से जूझ रहा है। अभी विशेष वर्षा न होने पर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र कटिहार जिले के आमदाबाद ब्लाक स्थित ग्राम गुआगाची तथा आजमनगर ब्लाक में धवोल महानन्दा नदी के कटाव के कारण चिन्ताजनक हालत में है तो बरारी ब्लाक में जोनियां कटिबंध तथा टोपरा चौकिया पहाड़पुर तटबन्ध के चेन सं० शून्य से 200 तक में गंगा नदी के कटाव से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। महानन्दा तटबन्ध के धवोल ग्राम में तटबन्ध टूट गया है एवं उसी तटबंध के सिकटिया, बहारखाल एवं शेशपुरा में भयंकर कटाव जारी है। किसी समय भी तटबंध कट सकता है। इसलिए उन उसभी लोगों को बचाने के लए तत्काल कोई उचिबत व्यवस्था सरकार करे :

बाढ़ की उक्त स्थिति से निपटने के लिए काफी पहले एक योजना बनाई गई थी और उस के एस्टीमेट को भी अक्टूबर 1981 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही 10 महीने बीतने पर भी कोई कार्यान्वियन आज तक नहीं हो सका तथा बाढ़ का खतरा क्षेत्र की जनता के समक्ष उपस्थित हो गया। इस प्रकार की स्थिति के कारण वहां की जनता में रोष एवं क्षोम व्याप्त है जो स्वाभाविक भी है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि कटिहार जिले की जनता को बाढ़ की भयावह स्थिति से बचाने के लिए तत्काल कोई ठोस व्यवस्था करें तथा उन लोगों को रसद आदि भी पहुंचायें ताकि उन के सामने भुखमरी की स्थिति और अधिक पैदा न हो। इस के साथ ही बाढ़ का प्रकोप शान्त होने के तत्काल बाद ही उक्त योजना पर अमल शुरू कराया जावें ताकि भविष्य में बाढ के कारण होने वाले जन एवं धन के नुकसान से बचाया जा सके और वहां की जनता को भी कष्टों से मुक्ति मिल सके।

(v) Observing 17th September, the birthday of Periyar E. V. Ramaswamy as Social justice Day.

***Shri Jai Pal Singh Kashyap (Aonla)** : September 17 should be declared the Social Justice Day to honour the birthday of Thanthai Periyar. From 1922 to 1973 Thanthai Periyar had waged a relentless war on Vanashram dharma and the consequent social atrocities. He was born in Erode on 17th September. His birthday has become a day of jubliation among the people of the entire country. He sacrificed his life at the altar of service to the Scheduled Castas and backward classes and for their social equality and upliftment. His birthday September 17, should be dedicated to his memory as the Social Justice Day.

(vi) Alleged crisis in publishing industry due to high cost of paper.

***Shri Arjun Sethi (Bhadrak)** : I would like to raise the following matter of urgent public importance under rule 377. The Publishing Industry is facing serious crisis due to high cost of paper. The industry has been unable to obtain paper at concessional rate for text books during the last one year. The non-availability of paper led to the increase in the prices of the text books. The number of new publications has also come down.

It is regrettable that the paper prices have gone up 400 per cent over the last decade. This has resulted in a rise in prices of books, which had hit not only the general public but also the students, authors and, above all, the publishers themselves.

Unless the rise in prices of paper is checked the Government plan for spreading literacy and education will not be fully implemented. Therefore, the publishing houses should be supplied paper at

*The original speech was delivered in Tamil.

*The original speech was delivered in Oriya.